

प्रारंभिक परीक्षा

गांधी और टैगोर की गहरी असहमति

संदर्भ

रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर, महात्मा गांधी के साथ उनके वैचारिक मतभेदों पर चर्चा फिर से शुरू हुई, विशेष रूप से राष्ट्रवाद, चरखा और सामाजिक-राजनीतिक विचारों को लेकर।

टैगोर और गांधी के बीच असहमति

आयाम	टैगोर का दृष्टिकोण	गांधी का दृष्टिकोण
चरखा (कताई का पहिया)	यांत्रिक, कर्मकांडीय और अंध-अनुकरण को बढ़ावा देने वाला कहकर आलोचना की	इसे आत्मनिर्भरता, श्रम की गरिमा और नैतिक अनुशासन के प्रतीक के रूप में देखा
राष्ट्रवाद	आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी; विश्व मानवतावाद के पक्षधर थे	स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन-राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया
आधुनिकता और तकनीक	विज्ञान, खुलेपन और वैश्विक आदान-प्रदान का समर्थन किया	मशीनरी के सीमित उपयोग को प्राथमिकता दी; ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया
जन आंदोलन	डर था कि असहयोग से अंध-अनुकरण और अशांति पैदा हो सकती है	स्वतंत्रता के लिए जन-लामबंदी को आवश्यक माना
शिक्षा दर्शन	रचनात्मक, उदार और समग्र शिक्षा (शांतिनिकेतन मॉडल) के समर्थक थे	उत्पादक कार्य से जुड़ी बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) पर जोर दिया
सामाजिक दर्शन	व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की विविधता महत्वपूर्ण है	सादगी के माध्यम से सामूहिक अनुशासन और नैतिक सुधार
प्राकृतिक घटनाओं पर विचार	आपदाओं को नैतिक कारणों से जोड़ने को खारिज किया (तार्किक दृष्टिकोण)	कभी-कभी घटनाओं (जैसे बिहार भूकंप) को नैतिक/सामाजिक पापों से जोड़ा

टैक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (TARA) हथियार

संदर्भ

भारत ने 7 मई, 2026 को टैक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (TARA) का सफल प्रथम उड़ान परीक्षण किया, जो सटीक प्रहार क्षमता (precision-strike capability) में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

TARA के बारे में

- भारत की पहली **स्वदेशी ग्लाइड किट** जो पारंपरिक अनगाइडेड बमों को सटीक-निर्देशित हथियारों (सटीकता और सीमा को बढ़ाता है) में परिवर्तित करती है।
- **विकसित किया गया:** डीआरडीओ (अनुसंधान केंद्र इमारत, हैदराबाद) द्वारा भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से।
- **कार्य प्रणाली:** मुक्त पतन (free fall) के बजाय लक्ष्य की ओर ग्लाइड करने के लिए एरोडायनामिक लिफ्ट और ऑनबोर्ड गाइडेंस का उपयोग करता है, जिससे स्टैंड-ऑफ सटीक प्रहार (आधुनिक हवाई युद्ध की अवधारणा) सक्षम होता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **विस्तारित रेंज:** ग्लाइड क्षमता प्रहार दूरी को बढ़ाती है (अपेक्षित सीमा लगभग **150-180 किमी**)।
- **स्टैंड-ऑफ क्षमता:** विमान को दुश्मन की वायु रक्षा सीमा में प्रवेश किए बिना प्रहार करने की अनुमति देती है।
- **उच्च सटीकता:** जमीनी लक्ष्यों की बेहतर टारगेटिंग। (अपेक्षित सर्कुलर एरर प्रोबेबल (CEP) < **5 मीटर**)।
- **मॉड्यूलर डिजाइन:** मौजूदा बम इन्वेंट्री के साथ संगत (परिचालन लचीलापन)।
- **प्लेटफॉर्म एकीकरण:** भारतीय वायु सेना के विमानों से तैनात किया जा सकता है (आसान अंगीकरण)।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर

संदर्भ

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बुलेट ट्रेन' के रूप में जाना जाता है, अपने निर्माण के चरम चरण में है।

कॉरिडोर के बारे में

- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई (महाराष्ट्र) और अहमदाबाद (गुजरात) के बीच **508 किमी** की दूरी तय करती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL), जापानी तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएँ

- **मार्ग (508 किमी):** गुजरात में 348 किमी, महाराष्ट्र में 156 किमी, दादरा और नगर हवेली में 4 किमी कवर करता है, जो क्षेत्रीय संपर्क और संतुलित विकास सुनिश्चित करता है।
- **गति (320 किमी प्रति घंटा):** 320 किमी प्रति घंटा की परिचालन गति (डिजाइन गति 350 किमी प्रति घंटा) मुंबई-अहमदाबाद यात्रा समय को 6-7 घंटे से घटाकर मात्र 2 घंटे से कुछ अधिक कर देती है।
- **तकनीक:** उन्नत सिग्नलिंग, स्वचालित ट्रेन नियंत्रण और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ जापानी शिनकानसेन (E5/E10 श्रृंखला) का उपयोग करती है, जो वैश्विक स्तर की सेवा सुनिश्चित करती है।
- **ट्रैक:** पारंपरिक भारतीय रेलवे ट्रैक, जो ढीले पत्थरों (बैलस्ट) का उपयोग करते हैं, के विपरीत बुलेट ट्रेन जापानी **"J-slab" बैलस्टलेस ट्रैक** प्रणाली का उपयोग करती है।
 - "J-slab" बैलस्टलेस ट्रैक एक हाई-स्पीड रेलवे प्रणाली है जो अत्यधिक स्थिरता, सुरक्षा और सटीकता प्रदान करने के लिए पारंपरिक ढीले पत्थरों को एक ठोस, बहु-स्तरीय कंक्रीट संरचना से बदल देती है।

K-आकार की अर्थव्यवस्था(K-SHAPED ECONOMY)

संदर्भ

पश्चिम एशिया में युद्ध वैश्विक ईंधन और उर्वरक आपूर्ति को बाधित कर रहा है, जिससे कीमतें और जीवन यापन की लागत बढ़ रही है। इसने एक K-आकार का आर्थिक विभाजन पैदा किया है, जहाँ अमीर अपनी वास्तविक खपत बनाए रखते हैं जबकि गरीब अधिक खर्च करने के बावजूद कम उपभोग कर रहे हैं।

K-आकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

- K-आकार की अर्थव्यवस्था एक मंदी-पश्चात (post-recession) परिदृश्य को संदर्भित करती है जहाँ विभिन्न क्षेत्र बहुत अलग गति, पैमाने या समय पर रिकवरी करते हैं।
- विशेषताएँ
 - **अपसारी पथ (Divergent Paths):** जब चार्ट बनाया जाता है, तो आर्थिक क्षेत्र दो दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो "K" अक्षर जैसा दिखता है।
 - **ऊपरी भुजा (Upper Arm):** उन क्षेत्रों या जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करती है जो तेजी से वापस पटरी पर आते हैं।
 - **निचली भुजा (Lower Arm):** उन समूहों का प्रतिनिधित्व करती है जो संघर्ष करते हैं या बहुत धीमी गति से रिकवरी करते हैं, जिससे समाज में स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं।

कारण:

- **पूर्व-विद्यमान असमानताएं:** मौजूदा असमानताएं अक्सर तब बढ़ जाती हैं जब कोई मंदी विभिन्न समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
- **सृजनात्मक विनाश (Creative Destruction):** मंदी के दौरान नई तकनीकों का उद्भव आधुनिक उद्योगों के पक्ष में हो सकता है जबकि पुराने उद्योगों को स्थायी रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।
- **नीतिगत पूर्वाग्रह:** विशिष्ट राजकोषीय या मौद्रिक सरकारी हस्तक्षेप अनजाने में कुछ उद्योगों को दूसरों की तुलना में लाभ पहुँचा सकते हैं।
- **वास्तविक आर्थिक झटके:** यदि मंदी किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए नकारात्मक झटके के साथ आती है, तो यह अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को स्थायी नुकसान पहुँचा सकती है जबकि अन्य अप्रभावित रहते हैं।

मनरेगा 2025-26: कवरेज और रोजगार में भारी गिरावट

संदर्भ

हाल ही में 'नरेगा संघर्ष मोर्चा' द्वारा जारी एक रिपोर्ट, जिसे 'लिबटेक इंडिया' द्वारा तैयार किया गया है, प्रतिस्थापन से पहले MGNREGS के अंतिम परिचालन वर्ष को कवर करती है।

मुख्य निष्कर्ष

- **रोजगार में गिरावट**
 - 44 लाख कम परिवारों को रोजगार मिला (↓8.2%)
 - 67 लाख कम श्रमिकों को रोजगार मिला (↓9.1%)
 - कुल मानव दिवस (persondays) 21.5% गिरे — 268.44 करोड़ से 210.73 करोड़
 - प्रति परिवार औसत मानव दिवस 50.18 से गिरकर 42.92 हो गया (↓14.5%)
- **100-दिन गारंटी अंतराल:** 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार 40.5% गिरे — 0.37 करोड़ से 0.22 करोड़।
- **आय की हानि**
 - औसत पारिवारिक आय ₹12,681 से गिरकर ₹11,460 हो गई
 - अनुमानित औसत आय हानि: ₹1,221 प्रति परिवार
 - कुल मजदूरी व्यय में ₹11,570 करोड़ की गिरावट आई

- राज्य-वार प्रदर्शन
 - सबसे खराब गिरावट: तमिलनाडु (42.8%), हरियाणा (41.7%), हिमाचल प्रदेश (41%), तेलंगाना (40.2%)
 - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले: झारखंड (+12.9%), जम्मू-कश्मीर (+7.3%), ओडिशा (+6.7%)
 - 20 में से 15 राज्यों में मानव दिवस में गिरावट दर्ज की गई

परिवर्तन संबंधी चिंता

- MGNREGS को विकसित भारत - ग्रामीण अधिनियम 2025 (दिसंबर 2025 में पारित) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है
- संक्रमण काल (transitional period) के लिए केवल ₹30,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- नई योजना बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के शुरू की गई — कार्यकर्ता संक्रमण के दौरान निर्बाध रोजगार का आग्रह कर रहे हैं।

मनरेगा बनाम विकसित भारत - ग्रामीण अधिनियम 2025

विशेषता	MGNREGA (पुराना ढांचा)	विकसित भारत - ग्रामीण अधिनियम (नया)
कार्य गारंटी	100 दिन	125 दिन
मजदूरी वित्तपोषण	100% केंद्रीय (अकुशल)	साझा (60:40 / 90:10)
बजटीय प्रकृति	विशुद्ध रूप से मांग-आधारित	मानक / आवंटन-आधारित
जवाबदेही	केंद्रीय रूप से प्रबंधित	साझा राजकोषीय उत्तरदायित्व

नीति आयोग ने निम्न छात्र प्रतिधारण और सीखने के परिणामों पर चिंता जताई

संदर्भ

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट "भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली - गुणवत्ता वृद्धि के लिए सामयिक विश्लेषण और नीति रोडमैप" ने भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रमुख संरचनात्मक और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को उजागर किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- उच्च माध्यमिक ड्रॉपआउट दर: लगभग 40% छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में विफल रहते हैं।
- संस्थागत विखंडन: केवल 5.4% स्कूल सभी ग्रेडों में निरंतर शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को संस्थान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और प्रतिधारण (retention) कम हो जाता है।
- असमान स्कूल वितरण: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त माध्यमिक सुविधाओं का अभाव है, जिससे यात्रा की दूरी लंबी होती है और ड्रॉपआउट का जोखिम बढ़ता है।
- शून्य-नामांकन वाले स्कूल: लगभग 7,993 स्कूलों में कोई छात्र नहीं है, जिसकी उच्चतम सांद्रता पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में है।
- अवसंरचना अंतराल: 1.19 लाख से अधिक स्कूलों में कार्यात्मक बिजली की कमी है, और एक तिहाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना हैं।
- व्यावहारिक शिक्षा का अभाव: लगभग आधे सरकारी माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी है, जबकि 'परख' (PARAKH) के निष्कर्ष वैचारिक अनुप्रयोग के बजाय रटने पर भारी निर्भरता दर्शाते हैं।
- सीखने के परिणामों में गिरावट: कक्षा 8 के केवल 45.8% छात्र बुनियादी भाग (division) हल कर सकते हैं, और कक्षा 6 के 30% से कम छात्र भिन्न (fractions) समझते हैं।

- **AI संबंधी चिंताएं:** कम उम्र में AI का अत्यधिक उपयोग आलोचनात्मक सोच को कमजोर कर सकता है; कक्षाओं में AI के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और नैतिक सुरक्षा उपायों की उल्लेखनीय कमी है।
- **अल्प-वित्तपोषण:** शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.6% है, जो कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 6% के लक्ष्य से कम है।

मुख्य सिफारिशें

- **बेलनाकार स्कूली शिक्षा (Cylindrical Schooling):** "संयुक्त विद्यालयों" (composite schools) में संक्रमण जो एक ही संरचना के भीतर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निर्बाध शिक्षा प्रदान करते हैं।
- **स्कूल परिसर:** NEP 2020 के 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल को लागू करना जहाँ एक माध्यमिक विद्यालय 5-10 किमी के दायरे में पास के प्राथमिक स्कूलों और आंगनवाड़ियों का समर्थन करता है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** PM eVIDYA, भारतनेट और PM गति शक्ति जैसी पहलों को एकीकृत करके समावेशी, अंतर-संचालनीय DPI बनाना।
- **प्रशासनिक भर्ती:** ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और क्लस्टर संसाधन समन्वयकों के रिक्त पदों को भरने के लिए समयबद्ध अभियान चलाना।
- **परिणाम-आधारित शिक्षा:** रटने से आगे बढ़ने के लिए बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और AI उपकरणों के नैतिक, संतुलित उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
- **राजकोषीय विस्तार:** बुनियादी ढांचे के उन्नयन, डिजिटल पहुंच के विस्तार और योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।

समाचार में स्थान: B1 (बिलकान) ब्रिज

संदर्भ

ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल संघर्ष के दौरान करज (Karaj) में B1 ब्रिज पर हमला किया गया।

पुल के बारे में

- **स्थान:** तेहरान के पश्चिम में करज में करज नदी पर स्थित है, जो प्रमुख B1 कॉरिडोर (महत्वपूर्ण शहरी-औद्योगिक जुड़ाव) का हिस्सा है।
- **कनेक्टिविटी:** तेहरान को उत्तर और उत्तर-पश्चिमी ईरान (कज़्विन, तबरीज, कैस्पियन क्षेत्र) से जोड़ता है और ईरान को रूस और मध्य एशिया से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों तक विस्तृत है।
- **क्षेत्रीय महत्व:** उत्तर-पश्चिम ईरान के अजेरी-आबादी वाले क्षेत्रों (करज और तबरीज क्षेत्र) को जोड़ने वाले कॉरिडोर पर स्थित है, जो इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
- **आर्थिक महत्व:** करज ईरान के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगर के रूप में कार्य करता है, और यह पुल औद्योगिक वस्तुओं की आवाजाही, रसद (logistics) और दैनिक यातायात (~200,000 वाहन) का समर्थन करता है।



मुख्य परीक्षा

शासन में डेटा मानकीकरण (DATA STANDARDISATION)

संदर्भ

डेटा उत्पादन में तीव्र वृद्धि के बावजूद, भारत की शासन संरचना (governance architecture) को प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

डेटा मानकीकरण

- **डेटा मानकीकरण** से तात्पर्य विभिन्न संस्थानों और विभागों में सूचनाओं को एक समान प्रारूप में एकत्र करने, संग्रहीत करने, संसाधित करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से है।
- यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पन्न डेटा सामान्य मानकों का पालन करे:
 - परिभाषाएं
 - प्रारूप (Formats)
 - वर्गीकरण प्रणाली
 - रिपोर्टिंग पद्धतियां

खराब डेटा प्रणाली और शासन से संबंधित चुनौतियां

- **अंतर-परिचालनीयता (Interoperability) का अभाव:** विभिन्न मंत्रालय और विभाग अक्सर एक-दूसरे से अलग डेटाबेस बनाए रखते हैं, जिससे समन्वय की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक दोहराव, कमजोर नीति समन्वय, कार्यान्वयन में देरी और अक्षम सेवा वितरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
 - **उदाहरण:** स्वास्थ्य सेवा, पोषण और टीकाकरण के लिए अलग-अलग डेटाबेस एक ही लाभार्थी के लिए अतिव्यापी (overlapping) जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
- **लाभार्थियों का दोहराव:** कमजोर सत्यापन तंत्र के कारण फर्जी प्रविष्टियां हो सकती हैं, जिससे राजकोषीय रिसाव (fiscal leakages), संसाधनों का गलत आवंटन और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया कल्याणकारी व्यय होता है।
 - **उदाहरण:** 'पहल' (PAHAL) योजना के तहत हटाए गए फर्जी एलपीजी कनेक्शन।
 - **उदाहरण:** पीएम-किसान (PM-KISAN) से हटाए गए अपात्र लाभार्थी।
- **परस्पर विरोधी आधिकारिक अनुमान:** विभिन्न विभाग एक ही मुद्दे के लिए विरोधाभासी आंकड़े रिपोर्ट कर सकते हैं।
 - **उदाहरण:** बचपन के तपेदिक (TB) के मामलों को 'स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली' (HMIS), रोग निगरानी प्रणाली और टीकाकरण डेटाबेस में अलग-अलग दर्ज किया जा सकता है, जिससे एक ही रोगी की कई बार गणना हो सकती है।
- **कमजोर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** असंगत और अविश्वसनीय डेटा वैज्ञानिक नीति निर्माण को कमजोर करता है, जिससे लाभार्थियों की गलत पहचान होती है और विकास योजना प्रभावित होती है।
- **संसदीय प्रश्नों पर अत्यधिक निर्भरता:** बुनियादी प्रशासनिक जानकारी अक्सर मानकीकृत सार्वजनिक प्रारूपों में उपलब्ध नहीं होती है, जो कमजोर सार्वजनिक डेटा अवसंरचना, पारदर्शिता की कमी और वास्तविक समय के शासन डैशबोर्ड के अभाव को दर्शाता है।

डेटा मानकीकरण का प्रभाव

- **कल्याणकारी दक्षता में सुधार:** मानकीकृत डेटाबेस लक्ष्यीकरण में सुधार करते हैं और दोहराव को कम करते हैं।

- **उदाहरण:** आधार (Aadhaar) से जुड़ी 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) प्रणालियों ने कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव को कम किया है।
- **रिपोर्ट संदर्भ:** सरकारी अनुमानों के अनुसार, DBT सुधारों ने फर्जी लाभार्थियों को हटाकर महत्वपूर्ण बचत में योगदान दिया है।
- **राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करना:** विश्वसनीय डेटाबेस फिजूलखर्ची को कम करते हैं और ऑडिटिंग प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं।
 - **उदाहरण:** डिजिटलीकरण और लाभार्थी सत्यापन ने खाद्य सब्सिडी और एलपीजी सब्सिडी प्रणालियों में दक्षता बढ़ाई है।
- **बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण:** एकीकृत डिजिटल सिस्टम जवाबदेही और समन्वय में सुधार करते हैं।
 - **उदाहरण:** कोविन (CoWIN) प्लेटफॉर्म ने कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन के दौरान अंतर-परिचालनीय और वास्तविक समय के डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व को प्रदर्शित किया।
- **आर्थिक विकास में सहायक:** कुशल डेटा प्रणालियाँ उत्पादकता और निवेश योजना में सुधार करती हैं।
 - **उदाहरण:** ओईसीडी (OECD) और विश्व बैंक जैसे संगठनों के अध्ययन बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा साझाकरण में सुधार से आर्थिक दक्षता और शासन परिणामों में वृद्धि होती है।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाना:** ओपन-डेटा सिस्टम लोकतांत्रिक निरीक्षण को मजबूत करते हैं।
 - **उदाहरण:** data.gov.in जैसे प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों को सरकारी डेटासेट तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं

- **एस्टोनिया का एक्स-रोड (X-Road) डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम:** एस्टोनिया ने सुरक्षित डेटा-साझाकरण वास्तुकला, परस्पर जुड़े सार्वजनिक डेटाबेस और वास्तविक समय के डिजिटल शासन के साथ दुनिया की सबसे उन्नत अंतर-परिचालनीय डिजिटल शासन प्रणालियों में से एक विकसित की है।
- **सिंगापुर की स्मार्ट नेशन पहल:** सिंगापुर ने शहरी शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के डेटा सिस्टम को एकीकृत किया है।
- **यूनाइटेड किंगडम का ओपन डेटा फ्रेमवर्क:** यह मानकीकृत और सार्वजनिक रूप से सुलभ सरकारी डेटासेट को बढ़ावा देता है।
- **यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क:** यूरोपीय संघ सदस्य देशों के बीच निरंतरता और तुलनात्मकता के लिए डेटा साझाकरण और डिजिटल शासन हेतु सामंजस्यपूर्ण मानकों को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **व्यापक राष्ट्रीय डेटा मानकीकरण ढांचा:** भारत को एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय राष्ट्रीय ढांचा बनाना चाहिए जो साक्ष्य-आधारित शासन को मजबूत करने के लिए सभी मंत्रालयों और राज्यों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, भंडारण और रिपोर्टिंग के लिए समान मानक निर्धारित करे।
- **डेटा गवर्नेंस के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना:** प्रस्तावित 'इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस' (IDMO) को कार्यप्रणाली में सामंजस्य स्थापित करने और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा गवर्नेंस हेतु केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए।

- **अंतर-परिचालनीय डिजिटल अवसंरचना:** सरकारी विभागों को अंतर-परिचालनीय डिजिटल सिस्टम बनाने चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और कल्याण जैसे क्षेत्रों में सूचनाओं के सुरक्षित और निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम करें।
- **ओपन डेटा और सार्वजनिक पहुँच:** भारत को व्यापक सार्वजनिक पहुँच के लिए वास्तविक समय के अपडेट, मानकीकृत मशीन-पठनीय प्रारूप और जिला-स्तरीय डेटासेट सुनिश्चित करके data.gov.in जैसे प्लेटफार्मों को मजबूत करना चाहिए।
- **सरकार के भीतर तकनीकी और सांख्यिकीय क्षमता:** सरकारी अधिकारियों के लिए डेटा प्रबंधन, सांख्यिकीय विश्लेषण, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- **जवाबदेही को संस्थागत बनाना:** शासन के आकलन और प्रशासनिक प्रदर्शन समीक्षाओं में डेटा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बननी चाहिए।

भारत की रक्षा मुद्रा में एक निर्णायक मोड़

संदर्भ

ऑपरेशन सिंदूर ने 'रणनीतिक संयम' (strategic restraint) से 'नपे-तुले बलप्रयोग' (calibrated coercion) की ओर स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया, जिसका उद्देश्य परमाणु दहलीज (nuclear threshold) के नीचे रहते हुए आतंकवाद को रोकना है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा रणनीति में बदलाव

- **सक्रिय सिद्धांत (Proactive Doctrine):** भारत अब विरोधी के व्यवहार को आकार देने के लिए अग्रक्रय (pre-emptive) और तत्काल दंडात्मक प्रहार करता है (पहले: हमलों के बाद विलंबित, प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाएं)।
- **त्वरित प्रहार क्षमता:** भारत तेज, लचीले और सटीक-आधारित "कोल्ड स्ट्राइक" (Cold Strike) ऑपरेशनों की ओर बढ़ गया है (पहले: धीमी लामबंदी और सीमित निष्पादन वाला कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत)।
- **राज्य की जवाबदेही:** भारत आतंकवादी समूहों और उनके राज्य प्रायोजकों को एक ही खतरे के रूप में देखता है, जिससे समर्थन संरचनाओं को सीधे लक्षित करना संभव हो गया है।
- **तनाव प्रबंधन (Escalation Management):** भारत ने सोपानिक प्रभुत्व (escalation dominance) बनाए रखते हुए परमाणु दहलीज के नीचे काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया (पहले: परमाणु भय ने सैन्य विकल्पों को प्रतिबंधित कर दिया था)।
- **संपर्क-रहित युद्ध (Non-Contact Warfare):** प्रहार करने के लिए ड्रोन, सटीक मिसाइलों, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की ओर बदलाव (पहले: पारंपरिक सैनिकों और तोपखाने आधारित संचालन)।
- **बहु-क्षेत्रीय संचालन (Multi-Domain Operations):** संचालन अब हवाई, जमीनी, साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को समन्वित तरीके से एकीकृत करते हैं (पहले: अलग-अलग, सेवा-विशिष्ट प्रतिक्रियाएं)।

ऑपरेशन सिंदूर का महत्व

- **दंड द्वारा विश्वसनीय निवारण (Credible Deterrence by Punishment):** विरोधी के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष और दृश्यमान लागत थोपकर, भारत ने निवारण को मजबूत किया और छद्म युद्ध (proxy warfare) की कीमत बढ़ा दी।
- **परमाणु ब्लैकमेल का कमजोर होना:** यह दर्शाता है कि सीमित पारंपरिक विकल्प व्यवहार्य बने हुए हैं, जिससे ढाल के रूप में परमाणु संकेतों पर निर्भरता कमजोर हुई है।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित युद्ध की परिपक्वता:** यह सटीक-निर्देशित हथियारों, ड्रोन, EW और साइबर की केंद्रीयता की पुष्टि करता है, जिससे बेहतर नियंत्रण के साथ उच्च-प्रभाव, कम-हताहत वाले ऑपरेशन सक्षम होते हैं।

- **इंटेलिजेंस-टू-स्ट्राइक संपीडन:** यह 'सेंसर-टू-शूटर' लूप को संकुचित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है—वास्तविक समय में ISR संलयन, AI-सहायता प्राप्त लक्ष्यीकरण और तेज कमान निर्णय।
- **रणनीतिक संकेत:** यह संकेत देता है कि गहराई और गोपनीयता अब सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, जिससे विरोधी की योजना बदल जाती है और इरादे की स्पष्टता द्वारा तनाव को रोका जाता है।

ऑपरेशन सिंदूर का राजनयिक संकेत

- **भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव:** पाकिस्तान की ओर अमेरिकी झुकाव और मध्यस्थता के प्रयासों ने दिखाया कि महाशक्ति साझेदारियाँ लेन-देन वाली (transactional) होती हैं, जो संकट के दौरान भारत की राजनयिक गतिशीलता को सीमित करती हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता का दावा:** भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध किया, जिससे विशेष रूप से क्षेत्रीय संघर्षों में द्विपक्षीयता और स्वतंत्र निर्णय लेने के अपने सिद्धांत को सुदृढ़ किया।
- **बहु-संरेखण (Multi-Alignment) की ओर झुकाव:** संकट ने किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए साझेदारी (अमेरिका, रूस, यूरोप, ग्लोबल साउथ) में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **जटिल भू-राजनीतिक वातावरण:** चीन-पाकिस्तान समन्वय और अमेरिका की भूमिका एक बहु-अभिनेता संघर्ष वातावरण का संकेत देती है, जिससे 'टू-फ्रंट' या हाइब्रिड युद्ध परिदृश्यों का जोखिम बढ़ जाता है।

रक्षा में संरचनात्मक मुद्दे

- **अपूर्ण संयुक्तता (पूर्ण थिएटर कमांड का अभाव):** खंडित कमान संरचनाएं बहु-क्षेत्रीय तालमेल को धीमा करती हैं, जिससे एकीकृत ऑपरेशनों का पूर्ण लाभ सीमित हो जाता है।
- **नए युग के क्षेत्रों में क्षमता अंतराल:** काउंटर-ड्रोन, स्तरीय वायु रक्षा, EW और ISR में कमियाँ रक्षात्मक लचीलापन और आक्रामक पहुंच दोनों को कम करती हैं।
- **आसूचना एकीकरण की कमी:** अपर्याप्त रूप से एकीकृत वास्तुकला से देरी और दोहराव होता है, जिससे त्वरित सटीक प्रहार क्षमता कमजोर होती है।
- **सूचना युद्ध (Information Warfare) की कमजोरी:** एक एकीकृत सिद्धांत और त्वरित-प्रतिक्रिया तंत्र की कमी विरोधियों को पहले विमर्श (narrative) गढ़ने की अनुमति देती है, जिससे कूटनीति प्रभावित होती है।
- **बल संरचना असंतुलन:** लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी और समर्पित लंबी दूरी के रॉकेट/मिसाइल बल की अनुपस्थिति निरंतर निवारण और गहरे-प्रहार (deep-strike) विकल्पों को बाधित करती है।

आगे की राह

- **संयुक्तता को संस्थागत बनाना:** एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theatre Commands) में तेजी लाना और निर्बाध, त्वरित संचालन सक्षम करने के लिए एक समर्पित लंबी दूरी की मारक क्षमता (रॉकेट/मिसाइल) कमान बनाना।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:** भविष्य के संपर्क-रहित, बहु-क्षेत्रीय संघर्षों की तैयारी के लिए ड्रोन, साइबर, AI, EW और अंतरिक्ष प्रणालियों में निवेश करना।
- **आसूचना वास्तुकला को मजबूत करना:** निर्णय लेने में देरी को कम करने और त्वरित सटीक प्रहार सक्षम करने के लिए वास्तविक समय की आसूचना संलयन प्रणाली (intelligence fusion systems) विकसित करना।
- **सूचना युद्ध सिद्धांत विकसित करना:** वैश्विक स्तर पर सत्य-आधारित, तेज और समन्वित विमर्श प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत संचार रणनीति बनाना।

- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाना:** आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और निरंतर युद्ध क्षमता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- **रणनीतिक बहु-संरेखण को अपनाना:** तकनीकी और राजनयिक समर्थन हासिल करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना।

